सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 278 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, बुधवार 18 नवम्बर, 2026
मूल्य ₹ 3/-





व्यस्त होने का मतलब हमेशा हकीकत में काम होना नहीं है।
-थॉमस ए. एडीसन

धोनी ने आईपीएल को कहा... 7 | महिला आरक्षण-परिसीमन पर सरकार... 3 | भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर... 2

अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा दावा

गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है भारत

बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को बताया बड़ी वजह

» नोटबंदी से वोटबंदी तक! दस साल के फैसलों का हिसाब मांगता बेरोजगार युवा और लोकतंत्र

» राहुल का कहना है कि मीडिया भले ही नजरअंदाज करे, लेकिन हकीकत यही है

» बीजेपी का पलटवार लीडर ऑफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बन चुके हैं राहुल गांधी

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और देश की मौजूदा स्थिति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भारत को गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा बताते हुए बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को बड़ी वजह बताया।

राहुल ने युवाओं के भीतर बढ़ती निराशा का जिक्र करते हुए एक ऐसा सवाल उठाया जो हर उस परिवार की चिंता बनता जा रहा है जहां बच्चे बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें लीडर ऑफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर राहुल गांधी ने किसी विदेशी धरती से ऐसा सवाल उठाया है जिसका धमका देश की सियासत में हुआ है।

“राहुल गांधी ने विदेशी धरती से ऐसा सवाल उठाया है जिसका धमका देश की सियासत में हुआ है।”

“भारत गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है शिक्षा व्यवस्था में गहरी चुनौतिया हैं और विनिर्माण क्षेत्र रोजगार पैदा करने की अपनी क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहा है।”



राहुल गांधी लीडर ऑफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा!

राहुल गांधी के बयानों की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी भारत विरोधी प्रचार (लीडर ऑफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा) के नेता बन गए हैं। भारत की प्रगति और भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनकी नफरत ही है जिसकी वजह से वह जब भी विदेश जाते हैं तो भारत के बारे में बुरा भला कहते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करती है वहीं दूसरी तरफ राहुल भारत को आर्थिक आपदा बता रहे हैं।

डिग्री है, हुनर है, सपने हैं बस नौकरी कहां है?

देश के नौजवानों के मन में उठ रहा यह सवाल अब घरों की चारदीवारी से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच गया है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने देश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल ने कहा है कि भारत गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है शिक्षा व्यवस्था में गहरी चुनौतियां हैं और विनिर्माण क्षेत्र रोजगार पैदा करने की अपनी क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उनके बयान का सबसे तीखा हिस्सा आर्थिक आंकड़ों से नहीं एक परिवार के भीतर बदलते संवाद से जुड़ा है। राहुल के मुताबिक आज नौजवान अपनें माता-पिता से सवाल कर रहे हैं कि जब आपके पास खुद स्थायी नौकरी नहीं है। जब आपकी पीढ़ी का अनुभव हमें रोजगार और सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं दे पा रहा है तो फिर आप हमें उसी रास्ते पर चलने की सलाह कैसे दे सकते हैं? यह सवाल केवल नौकरी का नहीं पीढ़ियों के बीच टूटते भरोसे का भी है। मोदी सरकार के दस साल से अधिक के कार्यकाल में आर्थिक फैसलों की लंबी फेहरिस्त रही है। नोटबंदी को कालेधन पर प्रहार और अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण का बड़ा कदम बताया गया। जीएसटी को एक देश एक कर की दिशा में ऐतिहासिक सुधार कहा गया। मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य सामने रखे गए। उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आयी जिससे कारोबार ठप हुए लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई और अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने की चुनौती खड़ी हुई। इन फैसलों के लाभ और लागत पर आज भी बहस जारी है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या देश की आर्थिक कहानी केवल विकास दर निवेश और बाजार की चमक से पूरी हो जाती है? या फिर उस नौजवान की आंखों में झांकना भी जरूरी है जो डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में भटक रहा है। राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक आरोप कहकर खारिज किया जा सकता है लेकिन रोजगार, शिक्षा, छोटे कारोबार और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े सवालों को खारिज करना आसान नहीं हैं।

भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर गैरकानूनी रूप से नाम जुड़वाने की चाल चल रही है : अखिलेश

» सपा प्रमुख बोले-उसके ख़िलाफ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर करारा वार किया है। उन्होंने लिखा कि भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर ग़ैरक़ानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके ख़िलाफ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा। यूपी के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- 'फार्म छह' की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी।

भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा। उन्होंने लिखा कि भाजपाई और उनके षड्यंत्रजीवी संगी-साथी उप्र में अपनी हार सामने देखकर विशेष खुफिया मुहिम चलाकर मतलब 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे' नाम के जरिए नकली वोट जोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं, उस पर हर एक बूथ से लेंकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित प्रत्याशी, प्रदेश से लेकर जिला व विधानसभा स्तर तथा हर वाहिनी के हर पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य, समर्थक व शुभचिंतक की हर एक नये वोट पर पैनी-गहरी नजर रहेगी।


सीएम योंगी के गढ़ गोरखपुर में सपा का रोड शो

हम एक-एक वोट का हिसाब भी माँगेंगे

कन्नौज सांसद ने लिखा कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सजग नागरिक अपने पड़ोस के नये जुड़नेवाले वोट पर निगाह रखे, हम एक-एक वोट का हिसाब भी माँगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे, और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के ख़िलाफ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे, पेंशन व फंड भी रुकवाएंगे और सजा भी दिलवाएंगे। उन्होंने लिखा कि भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर गैरकानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके ख़िलाफ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफआइआर भी कराई जाएगी. इस लोकतांत्रिक अपराध में संलिप्त हर किसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर सजा दिलवाई जाएगी।

नाजायज संपत्ति भी उनसे छीन लेगा..

सपा चीफ ने लिखा कि जब मुकदमा चलेगा और सजा होगी तो कोई भाजपाई इन दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएगा. अधिकारी याद रखें भाजपा किसी की सगी नहीं है. जब जेल में सजा भुगतते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी अकेले में बैठकर अपने किये पर पछता रहे होंगे उसी समय जेल के बाहर उनके परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों की उलाहना व कटाक्ष झेल रहे होंगे. जो भ्रष्ट अधिकारी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इतना कमा लिया है कि सात पुश्तें बैठकर खाएंगी तो वो ये याद रखें कि उनकी बेतहाशा बढ़ती जमीन-जायदाद पर भी जनता की निगाह है, जब जाँच होगी तो कानून उसकी नाजायज संपत्ति भी उनसे छीन लेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 पर क्या कहा है?

अखिलेश का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एक बयान में कहा कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और विवरण में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. इसके लिए फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से आवेदन करने का अवसर मिलेगा. 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे. पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे. साथ ही मतदाता सूची की प्रविष्टियों की शुद्धता पर जोर रहेगा. जनसंख्या के अनुमान के मुताबिक मतदाताओं की संख्या करीब 2 करोड़ कम है. इसमें महिला मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा कमी सामने आई है।

अखिलेश यादव महादेव का मंदिर बनवाकर करेंगे रामलला का दर्शन

» तेज नारायण पांडेय ने कहा सपा प्रमुख से बड़ा श्रीराम का अनुयायी कोई नहीं है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अयोध्या। प्रभु श्रीराम भी शिवजी के भक्त थे। जब उन्होंने रामसेतु की स्थापना की थी तो भगवान शिव की पूजा की थी। अखिलेश यादव भी शिवजी का मंदिर बनवाने का संकल्प पूरा करके रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में उनसे बड़ा श्रीराम का अनुयायी कोई नहीं है। यह बातें एक अखबार की खास बातचीत में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन ने कहीं।



उन्होंने बताया कि भागवत कथा के दौरान जब अखिलेश यादव से राम मंदिर दर्शन के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि पवन से कहेंगे कि कोई अच्छी तिथि निकलवाकर बताएं। इसके बाद उन्होंने गुरुजनों और श्रेष्ठजनों से विचार-विमर्श किया। उनकी ओर से 12 दिसंबर की तिथि बताई गई, जिसके बाद सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई। कहा कि अखिलेश यादव पहले भी कहते रहे हैं कि केदारेश्वर महादेव मंदिर बनने के बाद वह रामलला का दर्शन करने आएंगे। अब मंदिर का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। वहां करीब दो साल से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। नियमित आरती और भोग भी हो रहा है। कुछ निर्माण कार्य शेष हैं, जिन्हें पूरा कराने के बाद अखिलेश यादव अयोध्या आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वह स्वयं भी दर्शन करने जाएंगे।

संत समाज के कुछ लोगों की ओर से विरोध किए जाने के सवाल पर पवन पांडेय ने कहा कि अयोध्या के पूज्य संत-महंतों का आशीर्वाद अखिलेश यादव के साथ है। कई संत-महंत पहले भी अखिलेश और शिवपाल यादव के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। रामायण मेले में मुलायम सिंह यादव दो बार आए थे। उस समय राम मंदिर के अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद थे। विरोध करने वाले संतों का भी आदर और सम्मान है। किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। सभी संतों से यही अपेक्षा है कि वे आशीर्वाद दें।

दिसंबर में चुनावी अभियान शुरू करेगी कांग्रेस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अयोध्या। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस रामनगरी अयोध्या से अपने चुनावी अभियान का आगाज करेगी। पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना दो दिसंबर को अयोध्या से चुनावी बिगुल फूंकेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस की नजर पूर्वांचल की विधानसभा सीटों पर रहेगी। पार्टी इस कार्यक्रम के जरिये कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ ही क्षेत्र में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है।

प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर और सनातन से जुड़े मुद्दों को लेकर सियासी दलों की सक्रियता के बीच कांग्रेस भी अयोध्या से अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के धार्मिक स्थलों के दौरों और सनातन से जुड़े आयोजनों में भागीदारी के बाद अब कांग्रेस की ओर से भी रामनगरी में बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है। इससे पूर्वांचल में विपक्षी दलों की राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कमला नेहरू भवन स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में अयोध्या और अंबेडकरनगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें जनचौपाल की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर चर्चा हुई।

बसपा की अयोध्या सीट से चुनावी अभियान का आगाज करने की तैयारी

» तैयारियों में सबसे आगे पार्टी, आकाश आनंद संभालेंगे मोर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसमें बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सबसे आगे है। पार्टी की अब तक प्रदेश में कई जनसभाएं हो चुकी हैं और 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। बसपा के प्रचार अभियान की कमान राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने संभाल रखी है।



उन्होंने अगस्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी सभाओं की शुरुआत की थी। इसके तहत हाथरस के सादाबाद और गौतमबुद्धनगर के जेवर में जनसभाएं की थीं। हालांकि, इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय संयोजक पद से हटा दिया गया था, जिससे पार्टी का प्रचार अभियान कुछ समय के लिए थम गया। पार्टी में वापसी और दोबारा राष्ट्रीय संयोजक बनने के बाद उन्होंने फिर से सभाएं शुरू कर दी हैं। हाल ही में उन्होंने बिजनौर के बढ़ापुर, सहारनपुर के नकुड़ और बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं। इस दौरान कई सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित किए। पश्चिमी यूपी की सभाओं में उनके निशाने पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने सपा को पीडीए के नारे पर घेरते हुए भाजपा की बी टीम तक करार दिया।

यूपी में गठबंधन पर अभी फैसला नहीं : चिराग पासवान

लखनऊ। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को लखनऊ में यह घोषणा करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से लिया गया है। हालांकि, पार्टी किस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी या अकेले लड़ेगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल, संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।





भाजपा को बेरोजगारी पर चिंतन करना चाहिए : सुरेन्द्र राजपूत

पार्टी प्रवक्ता ने कहा, मथुरा में वाराणसी के कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को तोड़ रही है भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने भाजपा के चिन्तन शिविर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और योगी सरकार को चिन्तन यूपी में बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर करना चाहिए।

श्री राजपूत ने कहा कि करीब 70 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लेकिन योगी सरकार इसके लिए किसी तरह गंभीर नहीं है। 68,500 और 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आये दिन सड? पर आन्दोलन करने के लिए विवश हैं, आज प्रदेश के युवाओं को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होने कहा कि हर साल देश में दो करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली भाजपा के डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 13 लाख पहुंच चुका है लेकिन कोई भी युवा रोजगार नहीं पा रहा है कोई भी परीक्षा बिना पेपरलीक के योगी सरकार नहीं सम्पन्न करा पा रही है।

गुजरात और लखनऊ के नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई जोरों पर



कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का जिक्र करते हुए सवाल किया कि बीजेपी में किसकी चलेगी क्या इस पर चिंतन हो रहा है। गुजरात और लखनऊ के नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई जोरों पर है। मथुरा की चिंतन बैठक अमित शाह, सीएम योगी की आंतरिक कलह की चिंतन बैठक है, जिन कार्यक्रमों में सीएम योगी रहते हैं वहां राज्यपाल नहीं रहती, जहां राज्यपाल रहती है वहां सीएम योगी नहीं रहते। श्री राजपूत ने कहा कि अयोध्या में जमीन खरीद में घोटाला हुआ, मंदिर न्यास के चढ़ावे और चंदे में चोरी हुई। यह हिन्दुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि मथुरा कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसके पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान सैंकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

महिला आरक्षण-परिसीमन पर सरकार का फिर दांव, पर उखड़ेंगे पांव?

नंबर गेम बदला, फिर भी आसान नहीं होगी राह

» कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष देगा तनाव

» टीएमसी-शिवसेना के बागियों के समर्थन के बाद भी 40 सांसदों की चुनौती कायम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने का विचार कर रही है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसको लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सियासी रस्साकसी और मचमच मची है। हालांकि सरकार के सामने लोकसभा में 40 सांसदों की चुनौती अभी भी कायम है। महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि सरकार विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक जुटा लेगी।

सरकार के लिए इस बार परिस्थितियां बदली है। अप्रैल में विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार के प्रस्ताव को रोक दिया था और एनडीए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सका था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में टीएमसी और शिवसेना (उद्धव) के सांसदों के पाला बदलने के बाद लोकसभा में संख्याबल बदल गया है। डीएमके के इंडिया ब्लॉक से अलग होने के बाद विपक्षी खेमे की संख्या भी घटी है। इसके बावजूद सरकार के सामने संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने की चुनौती बनी हुई है। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ महिला आरक्षण लागू करने की नहीं, बल्कि परिसीमन के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे को गढ़ने की भी है। अप्रैल में एकजुट विपक्ष ने सरकार को रोक दिया था, लेकिन बदले हुए संख्याबल ने उसे नई उम्मीद दी है। हालांकि, भाजपा का 15-18 और वोट जुटाने का दावा अभी अनुमान ही है। दक्षिणी राज्य अमूमन इसके विरोधी रहे है। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए इन दोनों मुद्दों पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार शीतकालीन सत्र से पहले या इसी महीने एक विशेष संसद सत्र बुलाकर इन विधेयकों को दोबारा पारित कराने के लिए राजनीतिक दलों (अन्य छोटे दलों) से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। हालिया राजनीतिक समीकरणों में कुछ बदलाव भी देखे गए हैं।



एनडीए के खेमे में 321 सांसद

लोकसभा के मौजूदा गणित के मुताबिक, एनडीए के खेमे में कुल 321 सांसद हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं। इनमें टीएमसी के बागी 20 सांसद, शिवसेना के 13 सांसद भी शामिल हैं। इस तरह एनडीए का संख्याबल 321 तक पहुंच गया है। हालांकि, इसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं, जो सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करते।

इंडिया गठबंधन की लोकसभा में संख्या अब घटकर 183 पर

इंडिया गठबंधन की लोकसभा में संख्या पहले 232 थी, जो अब घटकर 183 रह गई है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के अलग होने के बाद उसके आठ सांसद बचे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के शिंदे गुट में जाने के बाद उसके तीन सांसद रह गए हैं। श्रीनगर के सांसद के इस्तीफे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व भी घटा है। तमिलनाडु में कांग्रेस के टीवीके को समर्थन के बाद 22 लोकसभा सांसद वाली डीएमके भी इंडिया ब्लॉक से अलग है। इन बदलावों के बाद लोकसभा में इंडिया ब्लॉक का संख्याबल 183 रह गया है।

डीएमके के 22 समेत 36 सांसदों पर नजर

सरकार के लिए सबसे अहम भूमिका उन 36 सासदों की हो सकती है जो न एनडीए में है और न ही इंडिया ब्लॉक में। इनमें डीएमके के 22 सांसद वाईएसआर कांग्रेस के चार, आम आदमी पार्टी के तीन, अकाली दल, पीएम, एएसपी, एआईएमआईएम के एक-एक सांसद और तीन निर्दलीय शामिल है। इनमें डीएमके का रुख सबसे महत्वपूर्ण होगा। पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग जरूर हो गई है, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर उसका सरकार के साथ आना आसान नहीं है।

प्रमुख बिंदु और वर्तमान स्थिति

विधेयक का उद्देश्य- सरकार संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 (राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35) करने और 2029 के आम चुनावों तक 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने का प्रयास कर रही है।

यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना पर आधारित प्रस्तावित है। अप्रैल 2026 में क्या हुआ था-अप्रैल 2026 में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत (352 वोटों की जरूरत थी, जबकि पक्ष में 298 वोट मिले थे) न मिलने के कारण यह संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया था। दक्षिण भारतीय राज्यों और विपक्ष का विरोध विपक्ष और खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने इस बात का विरोध किया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और सीटें बढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रण लागू करने वाले दक्षिण और पूर्वी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट सकता है और उत्तर के राज्यों का प्रभाव बढ़ सकता है।

विपक्ष को 36 सांसदों से उम्मीद

कांग्रेस के एक सांसद के मुताबिक 36 बिना खेमे वाले सांसदों में 28 इस बिल के विरोध में वोट कर सकते है। उम्मीद है कि डीएमके के 22, आप के 3, जेडपीएम,एएसपी, एआईएमआईएम के एक-एक सांसद भी है जो बिल के विरोध में वोट कर सकते है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में तीन दिन का विशेष सत्र बुलाने और विधेयकों को 15-18 वोटों के अंतर से पारित कराने का दावा किया है। याद दिलाया कि सरकार को 50 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था।

छह सांसद जुटाने की चुनौती

राज्यसभा में सरकार के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, उच्च सदन में एनडीए के पास 155 सांसदों का समर्थन है, जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 161 सदस्यों की जरूरत होगी। यानी सरकार यहां महज छह सांसद पीछे है। छह सासदों का समर्थन जुटाना सरकार के लिए लोकसभा के मुकाबले कम चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।

नया विधेयक बनाम पुराना विधेयक

दरअसल, महिला आरक्षण विधेयक जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है, उसे 2023 में ही संसद के दोनों सदनों में पारित किया जा चुका है और वो कानून भी बन चुका है। 106वें संविधान संशोधन के रूप में उस विधेयक को पारित कराने के लिए भी तत्कालीन सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था लेकिन विपक्ष के समर्थन से उस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल राज्यसभा सदस्य नेता कहते हैं, विधेयक पास कराने की सरकार की मंशा ही नहीं थी। वो तो यही चाहते थे कि कैसे इसके बहाने चुनाव के दौरान भाषण देने का मौका मिले। महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में ही पास हो चुका है, और सर्वसम्मति से पास हो चुका है। हम सबने उसे मिलकर पास कराया है. उस विधेयक में आपने देश से वादा किया था कि 2026 के बाद जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और फिर महिला आरक्षण की व्यवस्था तय की जाएगा। ये उनका संवैधानिक कर्तव्य था लेकिन सरकार उससे पीछे हट गई। दरअसल, 2023 में पारित संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन उस वक्त सरकार का कहना था कि इसकी व्यवस्था जनगणना और परिसीमन के बाद तय की जाएगी। लेकिन जब अचानक सरकार 131वां संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई तो विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगा। उसका कारण यह था कि सरकार अपने ही वादे से मुकर रही थी। यानी 2026 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बजाय, सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन कर रही थी। हालांकि विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति विधेयक के दूसरे हिस्से पर थी जिसके तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था।

जिद... सच की



Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_SanjayS

आम लोगों के मजबूत होने से देश होग मजबूत

जल, जंगल और जमीन की रक्षा से लेकर सामाजिक जागरण और राष्ट्र के स्वाभिमान तक, भगवान बिरसा मुंडा का जीवन भारतीय इतिहास की ऐसी प्रेरणागाथा है, जो आज भी देश को दिशा दिखाती है जो आज भी देश को दिशा दिखाती है।

कोई भी देश तब मजबूत होता है जब उसके सभी लोग मजबूत होते हैं। उनमें उस देश के आदिवासी, जनजाति, गरीबों का सुदृढ़ होना अवाश्यक है। जब कमजोर आदमी मजबूत होत है राष्ट्र भी समृद्ध व शक्तिशाली होता है। अभी भारत में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज के स्वाभिमान और ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करता है। केंद्र सरकार उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा करते हुए, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से जनजातीय वर्ग को विकास तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बना रही है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा से लेकर सामाजिक जागरण और राष्ट्र के स्वाभिमान तक, भगवान बिरसा मुंडा का जीवन भारतीय इतिहास की ऐसी प्रेरणागाथा है, जो आज भी देश को दिशा दिखाती है जो आज भी देश को दिशा दिखाती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही समृद्ध हमारी जनजातीय परंपराएं भी हैं। भारतीय इतिहास में जनजातीय समाज का योगदान केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के संरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

दुर्भाग्यवश, इतिहास के अनेक पन्नों में इन महानायकों के संघर्ष और बलिदान को वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार थे। इसी ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जनजातीय गौरव दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह दिन केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि देश के करोड़ों जनजातीय नागरिकों के स्वाभिमान, अस्मिता और गौरव को नमन करने का दिन है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा का जीवन असाधारण संघर्ष और अदम्य साहस की मिसाल है। उनके पिता सुगना मुंडा और माता करमी हातू ने आर्थिक कठिनाइयों के बीच उनका पालन-पोषण किया। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और सामाजिक चेतना से संपन्न बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी चुनौती उसकी जमीन, संस्कृति और पारंपरिक अधिकारों पर बढ़ता बाहरी हस्तक्षेप है। उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित किया, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई और शिक्षा, स्वच्छता, नैतिकता तथा सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

प्रदूषण मामलों में आपराधिक कानून के तहत हो कार्रवाई

डॉ. सुधीर कुमार

हर साल सर्दी की दस्तक के साथ ही देश के बड़े हिस्से, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तरी भारत में, हवा जहरीली होने लगती है। एक्यूआई का स्तर 400 और 500 के आंकड़े पार कर जाता है। इसका बड़ा कारण औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाने वाला उत्सर्जन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स द्वारा उड़ाई जाने वाली धूल है। सवाल है कि क्या केवल कुछ लाख रुपये का जुर्माना लगाकर इतने बड़े पैमाने पर लोगों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दी जा सकती है? दरअसल, जब उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन जानबूझकर और लगातार किया जाए, तो इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही न मानकर कॉर्पोरेट पर्यावरण अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाए।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 से लेकर 40 तक व्यवस्था करती हैं कि यदि कोई कंपनी या औद्योगिक इकाई तय मानकों का उल्लंघन करती है, तो उसके लिए जिम्मेदार डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स और शीर्ष प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से आपराधिक तौर पर जवाबदेह ठहराया जा सकता है। धारा 37 के तहत पांच से सात साल तक की जेल का प्रावधान है, वहीं धारा 40 सुनिश्चित करती है कि कंपनी के शीर्ष अधिकारी जिम्मेदारी से यह कहकर नहीं बच सकते कि उन्हें उल्लंघन की जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद, हकीकत में इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होना या किसी कॉर्पोरेट प्रमुख का जेल जाना बेहद दुर्लभ है। अधिकांश मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) सिर्फ आर्थिक दंड लगाकर मामले निपटा देते हैं। एनजीटी द्वारा लागू 'पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल' सैद्धांतिक रूप से मजबूत होने के बावजूद व्यवहार में कॉर्पोरेट्स के लिए आसान रास्ता बन गया है, क्योंकि बड़ी कंपनियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद जुर्माने की रकम को व्यापारिक खर्च या लाइसेंस लागत मानकर आसानी से चुका देती हैं।

इसलिए इस सिद्धांत को सख्त आपराधिक न्यायशास्त्र से जोड़ने की जरूरत है। भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में कानूनी नजीर पेश की। एमसी मेहता बनाम भारत संघ (1987) के प्रसिद्ध ओलियम गैस लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'एब्सोल्यूट लायबिलिटी' सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अदालत ने कहा था कि यदि कोई उद्योग खतरनाक गतिविधियां चलाता है और उससे जनता



को नुकसान होता है, तो उस उद्योग को बिना किसी छूट के पूरा मुआवजा देना होगा और उसकी जिम्मेदारी अटूट होगी। इसी तरह वेल्होर सिटीजंस वेलफेयर फोरम (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित किया था। कई विकसित देशों ने पर्यावरणीय क्षति को गंभीर आपराधिक कृत्य माना है। यूरोपीय संघ का एनवायरनमेंटल क्राइम डायरेक्टिव पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों को आपराधिक श्रेणी में रखता है, जहां कंपनियों पर न केवल उनकी वैश्विक कमाई का भारी हिस्सा जुर्माने के रूप में लगाया जाता है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों को लंबी जेल की सजा भी दी जाती है। विचारणीय यह कि कॉर्पोरेट पर्यावरण अपराधों का प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब कोई कंपनी जानबूझकर प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को बंद कर देती है या कचरा खुले में बहाती है, तो वह एक तरह से धीमी गति का जनसंहार कर रही होती है। कॉर्पोरेट क्राइम की इस अनूठी प्रकृति को समझते हुए कानूनी ढांचे में फेरबदल करने की सख्त दरकार है। वायु प्रदूषण से निपटने को आधुनिक कानूनी और तकनीकी उपाय जरूरी हैं। इसके तहत पहला प्रमुख सुझाव वायु अधिनियम, 1981 (धारा 37-40) के कड़े प्रवर्तन के लिए विशेष 'कॉरपोरेट एनवायरनमेंटल प्रॉसीक्यूशन सेल' गठित करने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए बाध्यकारी बनाने तथा बार-बार उल्लंघन करने वाली कंपनियों की व्यावसायिक इकाइयों को पूरी तरह बंद करने का है।

दूसरे समाधान के रूप में रीयल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग और फॉरेंसिक एनवायरनमेंटल ऑडिट को कानूनन अनिवार्य करने की बात कही गई है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों के ऑटोमेटेड सेंसर उत्सर्जन सीमा पार होते ही स्वत: नोटिस जारी करेंगे और आपराधिक जांच शुरू होगी। तीसरे सुझाव में एनजीटी और आपराधिक अदालतों के बीच बेहतर समन्वय की वकालत की गई है, ताकि भारी जुर्माना लगाने के साथ ही जिम्मेदार कॉर्पोरेट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मामले को सीधे संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में हस्तांतरित किया जा सके।

स्कूलों को सुरक्षित बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी

डॉ. पुनीत अरोड़ा



विद्यालय को बच्चे का दूसरा घर कहा जाता है। माता-पिता जिस विश्वास के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसकी बुनियाद इस भरोसे पर होती है कि वहां उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब विद्यालय परिसर में ही किसी बच्चे की जान पर बन आए, तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, संस्थागत जवाबदेही और सामाजिक चेतना की परीक्षा बन जाती है। पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित विद्यालय में बीते दिन हुई घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। तीसरी कक्षा के आठ वर्षीय छात्र ने केजी में पढ़ने वाली छह वर्षीय बच्ची पर कथित रूप से ईंट और अन्य वस्तुओं से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा किए गए विद्यालय परिसर के निरीक्षण में कई प्रश्न सामने आए।

इन प्रश्नों के उत्तर निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आने चाहिए। वहीं, शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों और प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है तथा जांच समिति गठित की गई है। पुलिस ने भी कथित लापरवाही के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस घटना में पीड़ित बच्ची के साथ-साथ कथित रूप से हमला करने वाला आठ वर्षीय छात्र भी कानून की दृष्टि में बच्चा है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 20 सात वर्ष से कम आयु के बच्चे के आपराधिक कृत्य को संवेदनशील ढंग से देखती है, जबकि धारा 21 के अनुसार, सात से बारह वर्ष के बच्चे के मामले में यह देखना आवश्यक है कि उसे अपने कृत्य की प्रकृति और परिणाम समझने की पर्याप्त परिपक्वता थी या नहीं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का मूल उद्देश्य दंड के बजाय सुधार और पुनर्वास है। अत: बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, पारिवारिक वातावरण की पड़ताल और उचित परामर्श आवश्यक हैं। यदि उसके व्यवहार को लेकर पहले शिकायतें थीं, तो यह भी जांचना होगा कि समय रहते उसे सहायता क्यों नहीं मिली।

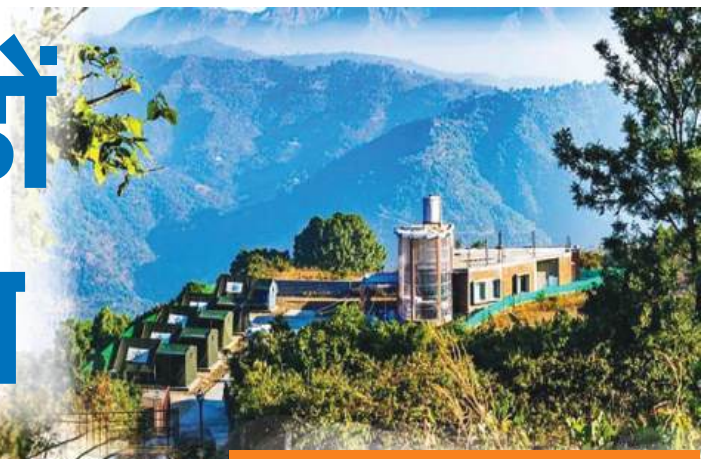
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाती है, जबकि धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्यों को निर्धारित करती है। प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है कि विद्यालय में प्रभावी निगरानी, ड्यूटी रोस्टर, अनुशासन और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था हो। शिक्षकों का दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि बच्चों के व्यवहार में असामान्य बदलाव और संभावित जोखिम के संकेतों को पहचानना भी है। बच्चे का व्यक्तित्व केवल विद्यालय में नहीं बनता। परिवार उसकी पहली पाठशाला है। इस घटना के संदर्भ में बच्चे के ऑनलाइन गेम खेलने और उससे प्रभावित होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, किसी गेम को घटना का प्रत्यक्ष कारण मान लेना उचित नहीं होगा। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। फिर भी यह पहलू हमें बच्चों के डिजिटल जीवन और स्क्रीन पर उपलब्ध सामग्री के प्रभाव पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करता है। दूसरी ओर, शहरों में बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित मैदान और खुले स्थान लगातार कम होते जा रहे हैं।

खेल के मैदानों की कमी बच्चों को घरों के भीतर और मोबाइल स्क्रीन तक सीमित कर रही है। खेल केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, टीम भावना, हार-जीत स्वीकार करने और गुस्से पर नियंत्रण रखने की शिक्षा भी देते हैं। सरकार, नगर निकायों, आरडब्ल्यूए और विद्यालयों को बच्चों के लिए सुरक्षित खेल मैदान और रचनात्मक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। माता-पिता को भी बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए तथा उन्हें आउटडोर खेल, पुस्तकें, संगीत और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। मीडिया ने इस घटना के माध्यम से विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज का बार-बार प्रसारण और सोशल मीडिया पर उसे वायरल करना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और निजता के लिए नुकसानदेह है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 किसी बच्चे की पहचान उजागर करने वाले विवरण और तस्वीरों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाती है।

यह संरक्षण पीड़ित और कानून के उल्लंघन के आरोप का सामना कर रहे, दोनों बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घटना से सबक लेने की भी आवश्यकता है। राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों का नियमित बाल-सुरक्षा ऑडिट हो। प्रारंभिक कक्षाओं में पर्याप्त सहायक कर्मचारी तैनात किए जाएं। प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित काउंसलर अथवा विशेषज्ञों से परामर्श की व्यवस्था हो। सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी हो। बच्चों में आक्रामक व्यवहार, तनाव और हिंसक प्रवृत्तियों के शुरुआती संकेतों की पहचान कर समय रहते सहायता दी जाए। प्रत्येक स्कूल में दुर्घटना और हिंसा की स्थिति में चिकित्सा सहायता, अभिभावकों को सूचना तथा शिकायत निवारण का लिखित प्रोटोकॉल अनिवार्य रूप से लागू हो। यह घटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की परीक्षा है। जब एक बच्चा हिंसा का शिकार हो और दूसरा बच्चा हिंसक व्यवहार करे तो उत्तर केवल दंड या आक्रोश नहीं, बल्कि जवाबदेही, संवेदना और सुधार होना चाहिए।

दिल्ली के पास इन जगहों पर बनाएं घूमने का प्लान

दिल्ली की भागदौड़ से दूर कहीं शांत जगह पर जाने का मन है, तो दिल्ली-एनसीआर से कई खूबसूरत जगहों का प्लान बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए हमेशा लंबी छुट्टी लेने या महंगी ट्रिप बुक करने की जरूरत नहीं होती। दिल्ली के आसपास ऐसी कई जगहें हैं जहां आपको एक ही ट्रिप में पहाड़, झील, जंगल और हरियाली का अनुभव मिल सकता है। उत्तराखंड के लैंसडाउन और ऋषिकेश से लेकर हरियाणा के मोरनी हिल्स और राजस्थान के सरिस्का तक, हर जगह का अपना अलग आकर्षण है। कहीं पहाड़ों के बीच सुबह की शुरुआत होती है तो कहीं जंगल सफारी और झील के किनारे शाम बिताने का मौका मिलता है। तो अगर आप दिल्ली से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो इन जगहों पर जरूर जाएं। बजट कम रखना हो तो सार्वजनिक परिवहन और साधारण ठहरने की जगह का विकल्प चुना जा सकता है।



मोरनी हिल्स, हरियाणा

यहां पहाड़ और झील दोनों का अनुभव मिल सकता है। दिल्ली से मोरनी हिल्स एक अच्छा विकल्प है। पंचकूला जिले में स्थित यह हरियाणा का प्रमुख हिल स्टेशन है। यहां पहाड़ियों के साथ टिक्कर ताल की खूबसूरती देखने को मिलती है। झील के आसपास हरियाली और पहाड़ी वातावरण आपको शहर की भीड़ से अलग अनुभव देता है। दो दिन की ट्रिप में यहां घूमना और आसपास के इलाकों को देखना संभव है।

ऋषिकेश

पहाड़, गंगा और एडवेंचर का अनुभव एक साथ लेने के लिए ऋषिकेश बेहतरीन जगह है। अगर आपकी लिस्ट में पहाड़ों के साथ नदी और रोमांच भी शामिल है, तो ऋषिकेश को चुना जा सकता है। दिल्ली से बस के जरिए यहां पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। गंगा किनारे घूमने, घाट देखने और आसपास के पहाड़ी इलाकों का आनंद लेने के अलावा यहां ट्रेकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां भी लोकप्रिय हैं।

लैंसडाउन और नैनीताल

शांत पहाड़ और जंगल के बीच सुकून की छुट्टियां बिताने के लिए लैंसडाउन खूबसूरत जगह है। उत्तराखंड का लैंसडाउन उन लोगों के लिए आकर्षक विकल्प है जो भीड़भाड़ से दूर शांत पहाड़ी माहौल चाहते हैं। देवदार के पेड़, पहाड़ी रास्ते और आसपास के जंगल इसे खास बनाते हैं। यहां वीकेंड पर जाने के लिए बस या साझा टैक्सी जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा लंबा सफर करने को तैयार हैं तो नैनीताल में आपको पहाड़ और झील दोनों मिलेंगे। नैनी झील के आसपास घूमना, माल रोड पर समय बिताना और पहाड़ी नजारों का आनंद लेना वीकेंड को खास बना सकता है।

सरिस्का

दिल्ली के आसपास जंगल सफारी के साथ वीकेंड ट्रिप का आनंद लेने के लिए सरिस्का जा सकते हैं। अगर आपको पहाड़ों से ज्यादा जंगल पसंद हैं, तो राजस्थान का सरिस्का अलग अनुभव देगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी इसका प्रमुख आकर्षण है। आसपास ऐतिहासिक स्थलों और अरावली के प्राकृतिक वातावरण को भी देखा जा सकता है।



हंसना मना है

टीचर- एक औरत एक घंटे मे 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें एक घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी....बच्चा- एक भी नही, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी...! बच्चे की बात सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है...

पप्पू दुकान में जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था, आलू ले लो आलू ले लो... राहगीर- लेकिन ये तो जलेबी है, पप्पू- चुप हो जा! वरना मक्खियां आ जाएंगी।

वकील- हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द? पत्नी- मेरा चश्मा कहां है संगीता...? वकील - तो इसमें मारने वाली क्या बात थी...पत्नी- मेरा नाम रंजना है! पूरा कोर्ट खामोश...

एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं...! पता करने पर पता चला कि गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है...!!!

यमराज (औरत से)- चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। औरत- बस दो मिनट दे दो। यमराज- दो मिनट में ऐसा क्या कर लोगी... औरत - फेसबुक पर स्टेटस डालना है, यह सुनकर यमराज ही हो गए बेहोश...!!!

कहानी | नटखट परी और जादुई गुफा

एक समय की बात है एक बहुत ही नटखट परी थी। वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी। यह सोचकर वह अपने सभी लोगों से अलग हो गई। वह हर दिन बहुत दूर-दूर तक जाती और नए लोग व नई दुनिया देखती थी। एक दिन वह उड़ती हुई एक घर के पास पहुंची। वहां पर वह खिड़की के पास छिप गई। उसने देखा उस घर में एक लड़का अपनी मां से जिद कर रहा था कि उसे परी देखना है। उसकी मां उसे समझा रही थी कि परियां सिर्फ आसमान में रहती हैं। जब आसामान पूरी तरह से साफ हो जाए, तब तुम उन्हें देख सकते हो। अभी रात हो गई है सो जाओ और सुबह जब आसामन साफ होगा तो परी को देख लेना। मां की बात सुनकर वह लड़का सोने लगता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। तभी खिड़की पर उसे नटखट परी दिखाई देती है। वह उसे घर के अंदर लेकर आता है। उसने देखा वह नटखट परी बहुत ही छोटी है। दोनों साथ में खेलने लगते हैं। नटखट परी उसे अपना जादू दिखा रही थी और वह लड़का भी खुश होकर नाचता। तभी लड़के के कमरे इस तरह की शोर सुनकर वहां पर उसकी मां आने लगती है। लड़का नटखट परी से कहता है कि अब तुम्हें यहां से जाना होगा। मेरी मां आ रही हैं। लड़के की बात सुनकर नटखट परी वहां से उड़ जाती है और लड़का चुपचाप लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। जब मां ने दरवाजा खोला तो देखा उसका बेटा तो सो रहा है। उसने सोचा उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वह भी अपने कमरे में सोने चली गई।

कहानी से सीख - हर किसी में एक नटखट और शरारती पन छिपा होता है। फिर चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी।

7 अंतर खोजें





पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष ऑफिस में अनावश्यक तनाव से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। कारोबारी यात्रा के अवसर मिल सकते हैं और नए ऑर्डर के लिए प्रयास कर सकते हैं।

वृषभ लंबे समय से रुके काम पूरे करने पर ध्यान दें। व्यापारिक विस्तार के नए अवसर तलाश सकते हैं। दोस्तों के साथ मुलाकात आनंददायक रह सकती है।

मिथुन ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है। व्यापार में रुके हुए प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं।

कर्क सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट में रुचि बढ़ेगी। दूरदराज के संपर्कों से व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। धन से जुड़े अवसरों का आकलन करके आगे बढ़ें।

सिंह काम में अड़चन आने पर धैर्य से काम लें। लेनदेन के मामलों में स्पष्टता बनाए रखें। ससुराल या परिजनों से बातचीत में संयमित भाषा का इस्तेमाल करें।

कन्या टीमवर्क से बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। साझेदारी के कारोबार में नए अवसरों का आकलन करें। आय और खर्च का संतुलन बनाए रखें।

तुला कार्यस्थल पर विरोधियों से सावधान रहें और अपने काम में स्पष्टता रखें। कानूनी या कागजी कार्रवाई सावधानीपूर्वक पूरी करें। योग और व्यायाम नियमित रखें।

वृश्चिक आपकी रचनात्मकता और काम करने का तरीका अधिकारियों को प्रभावित कर सकता है। शेयर बाजार या नए क्षेत्रों में निवेश से पहले जोखिम समझें।

धनु कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, शांत रहकर काम करें। रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में सावधानीपूर्वक निर्णय लें। आर्थिक लेनदेन में समझदारी से काम लें।

मकर नए प्रोजेक्ट में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। नए संपर्कों से कारोबार बढ़ाने की संभावनाएं तलाशें। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है।

कुम्भ वाणी पर संयम रखें और सहकर्मियों से अनावश्यक बहस से बचें। रुके हुए बकाए की वसूली के लिए प्रयास कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों को लेकर चर्चा हो सकती है।

मीन निर्णय लेने की क्षमता और कामकाज बेहतर बनाने पर ध्यान दें। व्यापार विस्तार के नए रास्तों पर विचार कर सकते हैं। दांपत्य और पारिवारिक जीवन में संवाद बनाए रखें।

रोडीज रीबर्थ शो में हुई रघु की वापसी

रघु राम निस्संदेह रियलिटी शो रोडीज के सबसे लोकप्रिय जजों में से एक हैं। वह शो के पहले सीजन से लेकर 11वें सीजन तक इसका हिस्सा रहे और 2014 में इसे छोड़ दिया। अब 12 साल बाद वह शो के 21वें सीजन रीबर्थ के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी वापसी की घोषणा के लिए सोमवार को मुंबई में एक इवेंट आयोजित किया गया था। रघु राम रोडीज में एक नए ट्विस्ट के साथ दस्तक देने वाले हैं। रियलिटी शो में अपने सख्त रवैये और दमदार मौजूदगी के लिए मशहूर ये अभिनेता और टीवी प्रेजेंटर अब रोडीज रीबर्थ के नए सीजन में लौट रहे हैं। रघु ने 2014 में अपने भाई राजीव राम के साथ शो छोड़ दिया था, जिसका कारण उन्होंने प्रोड्यूसर्स का दखल बताया था।



रोडीज रीबर्थ की रिलीज डेट

रोडीज रीबर्थ 16 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ। इसका हर एपिसोड शुक्रवार और शनिवार शाम 7 बजे MTV चैनल पर प्रसारित होगा। रोडीज रिबर्थ दर्शक दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप यह शो नेटफिलक्स और जियो हॉटस्टार पर एक साथ स्ट्रीम होगा। जहां प्रिंस नरूला, नेहा धूपिया और निखिल चिनप्पा गैंग लीडर्स के रूप में वापसी कर रहे हैं। वहीं रोडीज रीबर्थ में अभिषेक मल्हान, बसीर अली और बानी जे नए गैंग लीडर्स हैं।

इवेंट में रोडीज में अपनी वापसी के बारे में बात करते हुए रघु ने कहा, बीस साल बीत चुके हैं और अब हम अपने तीसरे दशक में कदम रख रहे हैं। पहले 10 सालों तक इसका एक खास फॉर्मेट था, लेकिन अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उस फॉर्मेट को खत्म करना जरूरी था। फिर नए गैंग लीडर्स आए और शो की लोकप्रियता और बढ़ गई। अब, जब हम अपने तीसरे दशक में एंट्री कर रहे हैं तो सब कुछ फिर से बदलने का समय आ गया है। इसीलिए मैंने रीबर्थ का विकल्प चुना है।

रघु राम ने आगे कहा, मुझे डर है कि कहीं गैंग लीडर्स थोड़े कंफर्टेबल न हो जाएं, क्योंकि वे सभी विजेता रहे हैं, इसीलिए वे गैंग लीडर्स हैं। उनमें से हर कोई शो जीतने की क्षमता रखता है। उनकी रणनीतियां पहले से तय हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं पूरा खेल ही बदल दूं? यह काफी दिलचस्प होने वाला है। इट्स टाइम टू शेक एवरीथिंग अप अगेन।

छठ के मौके पर एकता कपूर ने किया ऐलान, 'द वन' का आएगा सीक्वल

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर द वन इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही। खासतौर पर इसकी लोककथा और फिल्म में दिखी छठ पूजा की झलक ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसके गाने छठी मैया को तो काफी पसंद किया गया। अब एकता कपूर ने इस फिल्म की कहानी को एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। एकता कपूर ने आधिकारिक तौर पर द वन के सीक्वल यानी द वन 2 की घोषणा कर दी है। इस फिल्म के लिए बालाजी मोशन पिक्चर्स ने एक बार फिर TVF से हाथ मिलाया है। पहली फिल्म की सफलता के बाद, छठ पूजा के मौके पर एकता कपूर और टीवीएफ ने ये ऐलान किया। पहली फिल्म के साथ एकता कपूर ने दर्शकों को भारतीय लोककथाओं, पौराणिक कथाओं और अलौकिक रहस्यों की दुनिया से रूबरू कराया था और अब वह इस दुनिया को आगे बढ़ाने जा रही हैं।



एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड टीजर के साथ इस फिल्म का ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा के साथ एक नई झलक जारी की, जिसमें एक छोटी बच्ची एक रहस्यमयी जगह पर तितली का पीछा करती नजर आ रही है। इस दौरान उसके इर्द-गिर्द कुछ अलौकिक शक्तियां दिखाई देती हैं। वीडियो देखकर लगता है जैसे ये अलौकिक शक्तियां उस बच्ची का पीछा कर रही हैं। अंत में बच्ची की मासूम आंखों में तेज नजर आता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जो पहली फिल्म के क्लाइमेक्स की याद दिलाती है, जो दोनों कहानियों के बीच किसी संभावित संबंध की ओर इशारा करती है।

आलोचकों को भोजपुरी अभिनेत्री ने दिया करारा जवाब

अगर कुंवारा लड़का छठ कर सकता है तो कुंवारी लड़की क्यों नहीं : अक्षरा

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने छठ पूजा करने को लेकर हुई आलोचना पर जवाब दिया है। कई वीडियो में वह पानी में खड़ी होकर पूजा करती और नारंगी सिंदूर लगाए नजर आई थीं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अविवाहित होने के बावजूद महोत्सव में शामिल होने पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, जबकि अन्य ने इसे सिर्फ प्रचार का एक तरीका बताया। ट्रोल्स पर पलटवार करते हुए अक्षरा ने कहा कि उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि छठ पूजा जैसा पवित्र त्योहार भी किसी की आस्था पर सवाल उठाने का मौका बन गया है। सोमवार शाम, 16 नवंबर को इंस्टाग्राम स्टोरी पर अक्षरा ने हिंदी में लिखा, मैंने छठी मैया को अर्घ्य दिया और कुछ लोगों ने मेरे ब्याह की चिंता का अर्घ्य दे दिया। एक सवाल मेरा भी है -अगर कुंवारा लड़का छठ कर सकता है तो कुंवारी लड़की क्यों नहीं? कोई तर्क है तो बताइए, मैं जरूर। सुनुंगी। अक्षरा सिंह ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। अक्षरा ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए सवाल किया कि उन्हें उनकी आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आस्था उनके और छठी मैया के बीच का मामला है और इसके लिए उन्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। हाल ही में अक्षरा सिंह तब चर्चा में आई थीं, जब मुंगेर के दुर्गा पूजा महोत्सव में पवन सिंह ने अक्षरा के प्रति अपनापन जताते हुए पुरानी बातों के लिए माफी मांगी।





कियारा आडवाणी ने दिखाई बेबी शॉवर की झलक

कियारा आडवाणी ने अपने बेबी शॉवर की एक छोटी सी झलक फैंस के साथ शेयर की है और इस दौरान केक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक टेस्टी केक की तस्वीर शेयर करके इस सेलिब्रेशन की एक झलक दिखाई है। उनके परिवार के लिए यह मौका काफी खास है, लेकिन केक की सजावट ने फैंस के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है। वे इस सजावट से यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। एक्ट्रेस अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही हैं।

इस चॉकलेट केक पर बैंगनी और नीले रंग के खूबसूरत फूल लगे थे, जिनमें से एक गुलाबी फूल सबसे अलग दिख रहा था। हालांकि, कियारा ने बच्चे के जेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन रंगों के इस अनोखे कॉम्बिनेशन को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स सोच रहे हैं कि क्या वह अकेला गुलाबी फूल इस बात का इशारा है कि उनके घर एक बेटी का जन्म होने वाला है। एक्ट्रेस ने इस खास जश्न को भले ही निजी रखा हो, लेकिन इसकी छोटी सी झलक ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। कियारा-सिद्धार्थ के घर एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। ऐसा लगता है कि यह कपल लाइमलाइट से दूर अपने जीवन के इस खास दौर का भरपूर आनंद ले रहा है।

फिल्म निर्माता करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के सीजन 9 में कियारा ने अपने प्रेग्नेंसी के अनुभवों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने किन भावनात्मक और शारीरिक बदलावों का सामना किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती तीन महीने काफी मुश्किल थे, क्योंकि उन्हें जी मिचलाने और हार्मोनल बदलावों से गुजरना पड़ा। कियारा ने यह भी बताया कि शुरुआत में उन्होंने और सिद्धार्थ ने इस खबर को अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया था। हालांकि, जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके आस-पास महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। अपनी मां और सास को अपने साथ रखने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, मुझे महिलाओं की जरूरत है। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसी महिलाओं की जरूरत है, जो मुझे समझ सकें।

फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ का धमाकेदार कमबैक, तेनु लेके जाना की टीजर हुआ रिलीज

टाइगर श्रॉफ एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। मुंबई में हुई फायरिंग की घटना के करीब एक महीने बाद अभिनेता ने सोशल मीडिया पर वापसी की है। सोमवार को उन्होंने अपने अपकमिंग गाने तेनु लेके जाना का टीजर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। 18 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना के बाद यह उनका पहला सोशल मीडिया पोस्ट है। इस वीडियो में टाइगर ब्लैक टक्सीडो में अपने शानदार लुक और फिट बॉडी को फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ अभिनेत्री केतिका शर्मा भी दिखाई दे रही हैं। टाइगर की वापसी से उनके प्रशंसक काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

टाइगर श्रॉफ ने अपने नए गाने का टीजर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, एक और चांस, एक और डांस। अभिनेता के इस छोटे से संदेश को उनकी वापसी का संकेत माना जा रहा है। वीडियो में वह ब्लैक टक्सीडो पहने नजर आते हैं। उनके शानदार डांस मूव्स और सिक्स पैक एब्स भी टीजर का खास आकर्षण हैं। गाने में टाइगर अभिनेत्री केतिका शर्मा के साथ रोमांस करते दिखाई देंगे। टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ ने भी भाई की वापसी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी शेयर किया। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे कमेंट में लिखा, वो वापस आ गया. वहीं, अभिनेता के फैंस भी उन्हें लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर देखकर उत्साहित नजर आए। एक यूजर ने लिखा, हमारा हीरो वापस आ गया। दूसरे ने कमेंट किया कि लंबे समय बाद टाइगर को अपनी फीड पर देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। एक अन्य फैन ने लिखा, टाइगर 2.0 वर्जन लोड हो गया है।

टाइगर श्रॉफ का गाना तेनु लेके जाना आज टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज हो गया। यह साल 2009 में आई फिल्म जय वीरू के गाने तेनु ले का रीक्रिएटेड वर्जन है। ओरिजिनल गाने को ओमर इनायत ने अपनी आवाज दी थी। इसमें कुणाल खेमू और अंजना सुखानी नजर आए थे। अब नए वर्जन में टाइगर और केतिका शर्मा की जोड़ी दर्शकों का मनोरंजन करती दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर वापसी से पहले टाइगर अपने काम पर भी लौट चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता ने हाल ही में पुणे में जाह्नवी कपूर के साथ अपनी आगामी फिल्म लग जा गले के लिए चार दिनों तक एक गाने की शूटिंग पूरी की है। यह शूट पुणे के कल्याणी नगर स्थित एक लोकप्रिय पब में हुआ। इस डांस नंबर को मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने कोरियोग्राफ किया है।



युवाओं को नौकरी दो : सिंघार

बोले- ओरछा और गांधी सागर में कैबिनेट करने से कुछ नहीं होगा

» मोहन सरकार पर नेता प्रतिपक्ष का तीखा हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

ग्वालियर। ग्वालियर पहुंचे सिंघार ने सरकार की कार्यप्रणाली, रोजगार, किसानों की समस्या और विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार कभी ओरछा तो कभी गांधी सागर में कैबिनेट बैठक कर रही है, लेकिन इन बैठकों से आम जनता को क्या हासिल हो रहा है? सरकार को बताना चाहिए कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? उमंग सिंघार ने आउटसोर्स भर्ती, सरकारी विभागों में खाली पदों और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा।

उन्होंने नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि आखिर इन गंभीर विषयों पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के पांच दिवसीय सत्र की अवधि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या पांच दिन का सत्र प्रदेश की सात करोड़ जनता की समस्याओं पर चर्चा के लिए पर्याप्त है? उनका कहना था कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। वंही मध्यप्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें जनकल्याण और समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने के कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी। विकास के संकल्पों का मंथन कर जनकल्याण के फैसले लिए गए। सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।



बीजेपी की अंतिम पारी चल रही है

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने इस प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की अंतिम पारी चल रही है और अब कांग्रेस की बैटिंग का समय है।

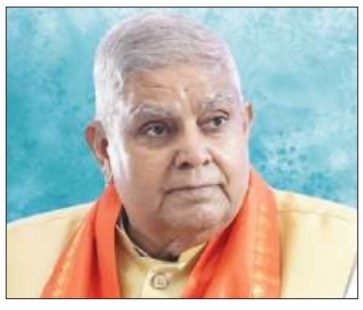
किसानों को खाद नहीं, हेलीकॉप्टर से उतरकर खेतों में जाएं

सिंघार ने खाद संकट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार के मुखिया को हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे खेतों में जाना चाहिए और किसानों से उनकी समस्याएं पूछनी चाहिए। केवल बैठकों और घोषणाओं से किसानों की परेशानी दूर नहीं होगी।

पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को अब तक नहीं मिला आवास

» राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने उठाए सवाल, बोले- किसी के फार्म हाउस पर रहना उचित नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क



जयपुर। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद छोड़ने के लंबे समय बाद भी प्रोटोकॉल के अनुरूप सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराए जाने का मुद्दा अब राजनीतिक चर्चा में आ गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति को पद की गरिमा के अनुरूप आवास उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने या इस्तीफा देने के बाद भी टाइप-8 बंगला उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर रह चुके व्यक्तियों को इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बावजूद जगदीप धनखड़ को अब तक सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उन्होंने कहा कि दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद उनके सरकारी बंगले को लेकर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। गहलोत ने सवाल उठाया कि आखिर धनखड़ कहां रह रहे हैं? किसी मित्र के फार्म हाउस पर रहना पूर्व उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास भी किया, लेकिन अब तक उन्हें यह पता नहीं चल पाया है कि धनखड़ को टाइप-8 बंगला देने का प्रस्ताव दिया गया है या नहीं। यहां तक कि टाइप-8 के बजाय टाइप-7 या टाइप-6 आवास देने को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारी है कि उनके कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति को अब तक आवास क्यों नहीं मिल पाया। इससे देश और दुनिया में क्या संदेश जाएगा? उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले लोग, प्रवासी भारतीय और राजस्थान के लोग भी पूर्व उपराष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते हैं।

न्यायपालिका ने प्रेस की स्वतंत्रता का व्यवहार में नहीं किया बचाव : सिब्बल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि न्यायपालिका ने सैद्धांतिक रूप में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की बात तो की है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमेशा ऐसा नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि अदालतों ने कई बार कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद हस्तक्षेप किया और सुरक्षा उपायों को लगातार एक समान तरीके से लागू नहीं किया। उन्होंने यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर 'क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका ने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की है?' विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि पत्रकारों को खबर लिखने के लिए हिरासत में लिए जाने, सूत्रों की पहचान उजागर करने के दबाव और कानूनी प्रक्रिया के ही सजा बन जाने की स्थिति में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर सवाल उठता है।



उन्होने कहा, संविधान ने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने विधि विरुद्ध रोकथाम अधिनियम सहित अन्य आपराधिक कानूनों के पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राथमिकी दर्ज होना, गिरफ्तारी का खतरा और लंबी कानूनी प्रक्रिया पत्रकारिता को हतोत्साहित कर सकती है। सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका ने प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत का बचाव तो किया है, लेकिन उसे व्यवहार में सुनिश्चित नहीं किया है। उन्होंने 2023 के 'मीडियावन' मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की आलोचना करने वाली खबरों को सत्ता-विरोधी करार देने से पत्रकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज की फेलोशिप से केजीएमयू के डॉ. सतीश सम्मानित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सतीश कुमार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ एडिनबर्ग की फेलोशिप एफआरसीपी से सम्मानित किया गया है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में 13 नवंबर को आयोजित अंतरराष्ट्रीय समारोह में विश्व के विभिन्न देशों के 64 चिकित्सकों को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। डॉ. सतीश की इस उपलब्धि ने देश के चिकित्सा जगत में गौरव का एक अध्याय जोड़ दिया है।

रॉयल कॉलेज के ऐतिहासिक परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता संस्थान के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मार्क स्ट्रेचन ने की। उन्होंने नवनिर्वाचित फेलोज को फेलोशिप डिप्लोमा प्रदान किए। चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट शैक्षणिक एवं व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए प्रदान की जाने वाली यह फेलोशिप वैश्विक चिकित्सा जगत में विशेष प्रतिष्ठा रखती है। वर्ष 1681 में स्थापित रॉयल कॉलेज ऑफ ह्यूफिजिशियंस ऑफ एडिनबर्ग विश्व के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शामिल है। लगभग 345 वर्षों की गौरवशाली परंपरा वाला यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सकीय प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।



» एडिनबर्ग में दुनियाभर के विभिन्न 64 चिकित्सकों को मिला सम्मान

» एफआरसीपी की उपलब्धि से अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका भारत का नाम

सोनिया गांधी नागरिकता विवाद पर कोर्ट सख्त

» एसएचओ से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के मामले को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर सख्त हो गई है.। कोर्ट ने बुधवार को सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट से जुड़े मामले में आईपी एस्टेट थाना एसएचओ से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

वकील विकास त्रिपाठी की ओर से 24 अगस्त 2025 को दाखिल की गई शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईपी एस्टेट थाना एसएचओ से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूची की मूल प्रमाणित कॉपियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।

धोनी ने आईपीएल को कहा अलविदा

» अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार बनाया चैंपियन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास लेकर अपने क्रिकेट करियर के एक बड़े अध्याय को खत्म कर दिया है। हालांकि, उनके इस फैसले के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस से किया गया एक खास वादा भी अधूरा रह गया। धोनी ने कहा था कि वह अपने करियर का आखिरी टी20 मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेलना चाहते हैं, लेकिन उनका आखिरी आईपीएल मुकाबला अहमदाबाद में हुआ था। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल सफर अब खत्म हो गया है।

अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार चैंपियन बनाने वाले धोनी ने मंगलवार को आईपीएल से संन्यास का एलान कर दिया। हालांकि, क्रिकेट से उनका जुड़ाव खत्म नहीं होगा। वह अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई से रिश्ता सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका जुड़ाव और वहां के फैंस का प्यार उन्हें इस शहर के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में शामिल करता है। चेपॉक स्टेडियम भी धोनी के लिए बेहद खास रहा है। उन्होंने कहा था कि वह अपने क्रिकेट करियर की प्लानिंग हमेशा से करते आए हैं। उनका आखिरी वनडे मुकाबला रांची में हुआ था और वह चाहते हैं कि आखिरी टी20 मैच चेन्नई में खेलें। धोनी ने कहा था, मैंने हमेशा अपने क्रिकेट की प्लानिंग की है। मेरा आखिरी वनडे मैच रांची में हुआ था। वनडे फॉर्मेट में मेरा आखिरी घरेलू मैच मेरे गृहनगर रांची में था। इसलिए उम्मीद है कि मेरा आखिरी टी20 मैच चेन्नई में होगा। यह अगले साल हो या पांच साल बाद, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। धोनी के इस बयान के बाद चेन्नई के फैंस को उम्मीद थी कि उन्हें अपने पसंदीदा खिलाड़ी का आखिरी मैच चेपॉक में देखने का मौका मिलेगा।



आईपीएल 2027 से पहले टीमों का बड़ा फैसला: कई बड़े नाम हुए रिलीज

नई दिल्ली। आईपीएल 2027 के लिए होने वाली मिनी नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी की है। आईपीएल के अगले सीजन के लिए 16 दिसंबर को गोवा में नीलामी होनी है। इससे पहले कुछ बड़े नाम का साथ टीम ने छोड़ दिया है। इनमें से अधिकतर चेहरों को नीलामी टेबल पर उतरना होगा। आईपीएल 2027 के लिए होने वाली मिनी नीलामी से पहले सभी 10 टीमों ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड और दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को रिलीज कर दिया है। वहीं, केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना को बाहर का रास्ता दिखाया है। सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर दिया। इन दोनों ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है।

बिहार में जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर सियासत गरमाई

» ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में घिरे बिहार सरकार के मंत्री

» राजद ने एनडीए सरकार पर उठाए सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को लेकर विवादों में हैं। यह विवाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले के तौर पर सामने आया है। यही वजह है कि अब उनकी बहाली पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी ने घेरा है। बुधवार (18 नवंबर, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने की मांग की।

मनोज झा ने अशोक चौधरी पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया। कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधान परिषद चुनाव में कथित धांधली का मुद्दा उठाया गया था। आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जुड़े एक दूसरे मामले पर चर्चा की जा रही है। दरअसल अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में कुछ महीने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया था। मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी ने नौकरी जॉइन करने के अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन दिया, उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है?19 अगस्त को यह मामला सिंडिकेट के समक्ष रखा गया। सिंडिकेट ने इसे राज्यपाल भवन को रेफर किया। राज्यपाल भवन की ओर से भी इस मामले में नियमों और कानूनी प्रावधानों पर सवाल उठाए गए।



विश्वविद्यालय शिक्षकों को विशेष लियन का अधिकार : मनोज झा



मनोज झा ने कहा कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) विश्वविद्यालय शिक्षकों को विशेष लियन का अधिकार देती है, लेकिन यह प्रावधान सदन के सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होने के मामले में लागू नहीं होता. आगे मनोज झा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले शिक्षक है और बाद में विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद बनता है, तो उसके लिए लियन का प्रावधान अलग हो सकता है, लेकिन यदि कोई सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होता है, तो उसे इस विशेष प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता।

जया बच्चन का किया उल्लेख

मनोज झा ने 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार के मामले का उल्लेख किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में स्पष्ट व्यवस्था दी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आर्थिक लाभ हुआ या नहीं, यह मुख्य आधार नहीं था, बल्कि पद ग्रहण करना ही अयोग्यता का आधार बना था। मनोज झा ने कहा कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री और एएन कॉलेज में शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में हैं। उन्होंने इसे कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया। मनोज झा ने राज्यपाल भवन की टिप्पणी पढ़ते हुए कहा कि यदि अशोक चौधरी विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जया बच्चन मामले के फैसले के आलोक में इसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए। उन्होंने राज्यपाल भवन की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में अयोग्यता का आधार बनता है और यह कानूनी रूप से गंभीर मामला है। मनोज झा ने कहा कि मामले को एडवोकेट जनरल के पास कानूनी राय के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि दो दिनों के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि सत्ता बचाने के लिए किसी कथित गैरकानूनी व्यवस्था को संरक्षण न दिया जाए और मामले में उचित कार्रवाई की जाए।

विपक्ष दिन रात पंजाब के किसानों को गाली देता है : अरविंद केजरीवाल

» आप नेता ने भाजपा-कांग्रेस को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क



चंड़ीगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले और प्रदूषण दो ऐसे मुद्दे हैं जिनपर सभी राजनीतिक दलों का फोकस है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्रीय मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है। दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत रात दिन पंजाब के किसानों को गाली देते रहते हैं।।

जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को लेकर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्डकी ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में प्रदेशभर में अब तक 6,516 आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 17 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं को लेकर अब तक 6,095 खेतों का निरीक्षण किया गया है। इनमें 2,621 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। वहीं, 297 खेतों में नॉन-एएफएल (नॉन-एक्स सीटू) से संबंधित मामले पाए गए हैं। इन मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) के तहत कुल 2,294 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 15 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।इसमें से 41 लाख 70 हजार रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के मामलों में अब तक 2,001 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 2,096 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। इसके अलावा, 35 मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीएक्यूएम एक्ट की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है।

हालांकि, रिपोर्ट में अभी तक किसी अधिकारी को चार्जशीट जारी करने या निलंबित करने का मामला दर्ज नहीं है। वहीं, नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 1,615 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं। पटियाला जिले में धान की कुल 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद जिले में पराली जलाने की 417 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 373 खेतों का निरीक्षण किया गया और 237 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। जिले में पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 178 मामलों में 8 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 3 लाख 15 हजार रुपये वसूल किए जा चुके हैं। पटियाला में पराली जलाने के मामलों में 225 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 152 राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। वहीं, जिले के नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 390 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।

एनटीपीसी के निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट साइट पर हादसा, तीन मजदूरों की मौत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चतरा। जिले के टंडवा में स्थित एनटीपीसी के उत्तरी कर्णपुरा मेगा विद्युत ताप परियोजना की निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। बुधवार को करीब 11.45 बजे यह घटना हुई है। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर ही तीन मजदूरों की मौत होने की सूचना है, जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं।

घायलों को तत्काल इलाज के लिए टंडवा स्थित संजीवनी हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि फिलहाल मृतकों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा एनटीपीसी के सीएचपी जेएच-1 लोकेशन पर हुआ, जहां कन्वेयर बेल्ट निर्माण का कार्य चल रहा था। इस परियोजना का ठेका एनटीपीसी की ओर से थायसन कंपनी को दिया गया है, जबकि निर्माण कार्य पेटी ठेकेदार सिंपलेक्स कंपनी के माध्यम से कराया जा रहा है।

हिंदू धार्मिक परंपरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची विजय सरकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर प्राचीन कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा खिलाफ थलपति विजय सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।

मंगलवार को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित पवित्र पत्थर के स्तंभ दीपाथून पर कार्तिगई दीप जलाने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी जाए, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि जिस जगह पर पवित्र दीप जलाने की अनुमति दी गई है, वह विवादित है और वहां पर कार्तिगई दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं रही है।

ईडी पर भड़के जज, बोले-आसमान नहीं टूट पड़ेगा

» आजम खान को जमानत मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।

राजू ने कहा कि आजम को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न दिए जाने की बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कल सुनवाई के लिए लगाने की बात कही। इस दौरान बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा, अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया।

इसके अलावा, गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज आजम खान को तामील कराए जाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने की ईडी की मांग पर भी विचार नहीं किया गया उन्होंने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित किया। ऐसा लग रहा था कि अदालत ने मामले का अंतिम फैसला ही सुना दिया हो।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाई कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी और इस दौरान केंद्रीय एजेंसी पर सख्त टिप्पणी की। आजम खान इस समय यूपी के डासना जेल में बंद हैं। उन्हें आज रिहा किया जाना है, ऐसे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिस तरह से उन्हें जेल के गेट पर ही श्वष्ठ ने हिरासत में लिया, वह मौजूदा कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है। कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।





महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। विधि सलाहकार: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा